

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

dissolved. But the same yardstick has not been applied in Andhra Pradesh to restore law and order nor was there any warning from the Union Government... (Interruptions)...

AN HONOURABLE MEMBER:  
Shame on the part of the ruling party!

DR. YELAMANCHILI SIVAJI:  
Nobody is there.

AN HONOURABLE MEMBER: All vacant!... (Interruptions)...

DR. YELAMANCHILI SIVAJI:  
During 1983 when there was a glut in tobacco market, firings took place and three tobacco growers were killed by the police firing at Tanguturu in the Prakasam District. Thereby the Andhra Pradesh Tobacco Growers Co-operative Society came into existence. That society helped the growers to give them relief whenever there was a glut.

Sir, due to the ad-hoc treatment by the Union Government as well as the slipshod attitude and quixotic attitude of the Union Government the production of the FCV tobacco in the country went down from 3 lakh metric tonnes to 75,000 metric tonnes this year. Even the 75,000 metric tonnes has not been properly utilised or exported for the economic welfare of the country.

When all the traders collude together and try to control the market, the Government agencies like the STC are conspicuously absent at the auction platforms to see that the prices are stabilised. This year the cost of production of tobacco went up at least 100 per cent compared to that of the last year due to erratic weather conditions and high prices of fertilizers like ammonium sulphate and others.

I would like to suggest that to stabilise and to safeguard the interests of the tobacco growers the State agencies like the STC may be pressed into action at the auction platforms. Tobacco yields about Rs. 200 crores of foreign exchange to the Union Government and more than Rs. 2,000 crores of excise duty to the exchequer. Unless the interests of the growers are safeguarded and protected, I am very much afraid that the country may have to pay a very high price by losing this excise tariff as well as the foreign exchange.

**Demand for giving representation to Oriya Film Producers and Directors in the Eastern Zonal Film Censor Board**

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa):  
Sir, my special mention is on harassment of the film-producers in the Oriya language.

Sir, you know, Orissa is culturally very rich and also it has great scenic beauty. In spite of that Oriya producers are not getting much preference in producing pictures in Oriya because of their economic conditions. There was a time when other producers, film producers from outside used to dub the Telugu, the Bengali and the Tamil pictures in the Oriya language, and for everything, for production and for direction, the Oriya film-makers were depending on outsiders. But now we have our own studio. We are having indoor and outdoor shootings also. We have facilities of recording. We are now able to make 15 to 20 pictures in a year. But we do not have anybody in the Eastern Zonal Film Censor Board. Therefore, even if the Oriya picture-makers spend so much of money, hardly two to three pictures are being passed by the Censor Board, and the rest of the producers face very miserable economic conditions.

Sir, my request, submission, through you, is that in the Eastern Zonal Film Censor Board, Oriya film-producers

and directors should be taken as Members, and they should be given sufficient opportunity to develop the Oriya pictures in future.

SHRI SARADA MOHANTY  
(Orissa): Sir, I associate myself.

Need to give matching grants by the  
Central Government to the States Minorities  
Financial Cooperations

श्री मोहम्मद खसरोलुर रहमान : (आन्ध्र प्रदेश) : वाइस चैयरमैन साहब, हमारे मुल्क की चंद रियासतों में अकलियतों की फला-बहबूदी के लिए उनकी पसमांदगी को दूर करने के लिए वहां की रियासत हुकूमतों ने माइनोरिटीज फाइनैशियल कारपोरेशंस कायम की हैं। चूनांचे आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार, गुजरात और कर्नाटक में इस किस्म के माइनोरिटीज फाइनैसिल कारपोरेशंस बनाय गये हैं और वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने एक लिमिटेड ग्रांट उन फाइनैस कारपोरेशंस को मंजूर की हुई है। हम देख रहे हैं कि जिन एम्स एंड ग्राज्जक्ट्स के तहत माइनोरिटीज फाइनैसिल कारपोरेशंस बनाये गये हैं उसकी तकमील गहीं हो रही है। जो रियासती हुकूमतों की जानिब से उन्हें ग्रांट मंजूर की गई है वह इन्तहाई नाकाफी है। जो माइनोरिटीज फाइनैसिल कारपोरेशंस बनाई गई हैं, जाहिर है कि वे कोई खास अग्राजो मकसद को सामने रखकर बनाई गई हैं लिहाजा उन अग्राजों मकसिद की तकमील के लिए जरूरी हैं कि वहां की रियासती हुकूमतें उन्हें खातिरखा इमदाद दे। रियासत हुकूमतों के मसाइल क्योंकि महदूद होते हैं इसलिए उन महदूद मसाइलों को सामने रखते हुए वहां की हुकूमतों ने जो इमदाद दी है वह इन्तहाई नाकाफी है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी उतनी ही मैचिंग ग्रांट अपनी जानिब से कायम फाइनानशल माइनोरिटीज कारपोरेशन को दे ताकि रियासती हुकूमतों की ग्रांट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो मैचिंग ग्रांट होती है उससे खातिरखा जमा होगी और जाहिर है कि वहां जो माइनोरिटीज के नौजवान

हैं उनकी मुआशी पसमांदगी और तालीमी पसमांदगी दूर हो सकेंगी। लिहाजा मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया से यह पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि जहां कहीं माइनोरिटीज फाइनानशल कारपोरेशन हैं वहां उन फाइनानशल कारपोरेशंस को मैचिंग ग्रांट खातिरखाइ मिकदार में दें। दूसरे हुकूमतें हिन्द से मुतालबा है कि वह सेन्ट्रल लबल पर खुद इस किस्म का एक माइनोरिटी फाइनानशल कारपोरेशंस बनाये और उसको काफी ग्रांट दे। यहां से भी माइनोरिटीज के जो नौजवान हैं उनकी माशी पसमांदगी और तालीमी पसमांदगी और उनके फला-बहबूद के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट का माइनोरिटी फाइनैस कारपोरेशन रहेगा तो उससे भी इमदाद मिलेगी। तीसरे मुतालबा यह है कि हम यह देख रहे हैं कि जो कुछ ग्रांट दी जा रही है वह जो फाइनैसिस कारपोरेशंस हैं 20 परसेंट मारीजल मनी के तौर पर खोन देती हैं। बाकी 80 परसेंट बैंकर्स को देना पड़ता है। माइनोरिटीज फाइनैसिस कारपोरेशंस ग्रांट 20 परसेंट मंजूर करने के बाद भी बैंकर्स उनके साथ प्रोपर्टी कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। माननीय यशवंत सिन्हा जी यहां नहीं हैं, मैं उनसे पुरजोर मुतालबा करना चाहता हूँ कि बैंकर्स के वजीरे फाइनैस, जितने हमारे नेशनलाइज्ड बैंकम के हैं उनको यह हिदायत दें कि जो कुछ माइनोरिटीज फाइनैसिल कारपोरेशंस हैं 20 परसेंट या मारीजल अमाउंट मंजूर करती हैं बाकी 80 परसेंट भी ग्रांट वह इन्हीं इंसारों को बैंकर्स दे और उनके साथ पूरा-पूरा ताबून करे।

†[شہری محمد خلیل الرحمان]

(آئندہوا: پردیو) : وائس چہر مہن  
صاحب - ہمارے ملک کی چلند  
ریاستوں میں اقتدار کی فلاح پروردی  
کہلئے انکی پسماندگی کو دور کرنے  
کے لئے وہاں کی ریاست حکومتوں  
نے مالدارانہ فائیدلشپل گارڈیوریشنس

Transliteration in Arabic Script